



## नितिन गडकरी ने बताया: हमास नेता इस्माइल हानिया से मुलाकात कुछ घंटे पहले, उनकी हत्या ने मलाई हुई घटना

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर अपनी अनुभव कहानी साझा की है। गडकरी ने बताया कि तेहरान में हानिया से मुलाकात उसी रात हुई थी जब उनकी हत्या हुई थी, और यह मुलाकात हत्या से सिर्फ कुछ ही घंटे पहले हुई थी। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर ईरान गए थे और वहाँ उन्होंने नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेस्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। समारोह के दौरान अनौपचारिक बातचीत में गडकरी हानिया से मिले थे। पत्रकारों को दिए बयान में गडकरी ने कहा कि जब उन्हें रात लगभग 1:15 बजे हानिया की हत्या की खबर मिली, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह घटना यह दिखाती है कि एक मजबूत देश को आसानी से नहीं छेड़ा जा सकता। हानिया की हत्या को हाल के वर्षों की सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में से एक माना जाता है। हानिया, जो हमास के राजनीतिक प्रमुख थे, तेहरान में ही मारे गए थे और इससे पश्चिम एशिया की राजनीति एवं सुरक्षा सामरिक चर्चाएँ बढ़ गई हैं। इससे क्षेत्रीय तनाव और भी बढ़ा हुआ है, और यह घटना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई सवाल खड़े कर रही है।

## कांग्रेस-उद्धव सेना में फूट: ठाकरे ने 'मविआ' की संभावनाओं पर लगाया विराम, पवार के NCP पर क्या कहा?



### संवाददाता | NEWS AGENCY

मुंबई-महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस और उद्धव ठाकरे-नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के रिश्तों में दरार की बात सामने आई है। उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी (MVA) गठबंधन के अस्तित्व और उसकी संभावनाओं पर ताज़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि 'मविआ' (MVA) के रूप में कांग्रेस-NCP-शिवसेना की पुरानी गठजोड़ की संभावनाओं को अब विराम मिल गया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों में कांग्रेस अलग-अलग रणनीति अपनाने पर विचार कर रही है। ठाकरे ने कहा कि इस समय गठबंधन का ढांचा उस रूप में नहीं कायम है जैसा पहले था, और शिवसेना (UBT) तथा अन्य राजनीतिक निर्णय अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे MVA के भीतर मतभेद उजागर हो रहे हैं। इस घटनाक्रम के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी (NCP) — विशेषकर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीयवादी पार्टी — की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि पवार का पार्टी विभाजन और ताज़ा राजनीतिक समीकरणों ने MVA के स्वरूप को बदल दिया है। राज्य में राजनीतिक विश्लेषक इस बदलाव को आगामी चुनावों की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं जहां गठबंधन और अलग-अलग मोर्चों दोनों की संभावना पर विचार किया जा रहा है, और यह कांग्रेस के लिए भी नए राजनीतिक फैसलों की चुनौतियाँ ला सकता है।

## कांग्रेस में "राहुल बनाम प्रियंका" की बहस तेज़: इमरान मसूद के बयान से सियासी हलचल बढ़ी

नई दिल्ली | कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व और भावी दिशा को लेकर गंभीर राजनीति चर्चा चल रही है, जो हाल के बयान के बाद और तेज़ हो गई है। इस बार चर्चाओं का केंद्र वायनाड से सांसद इमरान मसूद का बयान रहा, जिसमें उन्होंने प्रियंका गांधी वाड़ा को प्रधानमंत्री पद का संभावित चेहरा बताया। इससे पार्टी के भीतर और बाहर यह बहस उठ गई है कि क्या कांग्रेस भविष्य में राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को प्रमुख नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ा सकती है। मसूद ने कहा कि यदि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता, तो वे इंदिरा गांधी की तरह निर्णायक भूमिका निभातीं और बांग्लादेश जैसे मामलों पर कठोर निर्णय लेतीं। उन्होंने प्रियंका की तुलना अपने दादी इंदिरा गांधी से करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व की शैली मजबूत और निर्णायक है। हालांकि इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गहराई कि क्या कांग्रेस का भरोसा राहुल गांधी से कम हो गया है, और पार्टी में प्रियंका के लिए समर्थन बढ़ रहा है।

कि प्रियंका के राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हैं और लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए इच्छुक हैं, जिससे पार्टी में प्रियंका के प्रति उत्साह को और बल मिला है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह विवाद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व पर चल रही बहस का संकेत है, जो वर्तमान में पार्टी की चुनावी प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजनीति की चुनौतियों की पृष्ठभूमि में उभर रहा है। कांग्रेस ने अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय या बयान जारी नहीं किया है, लेकिन यह निश्चित है कि यह चर्चा कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व की दिशा को प्रभावित कर सकती है। समग्र रूप से इमरान मसूद का बयान, भाजपा की प्रतिक्रियाएँ, मसूद की सफाई और प्रियंका के समर्थकों की राय ने कांग्रेस के अंदर एक व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, जो आने वाले समय में पार्टी की रणनीति और नेतृत्व चयन को प्रभावित कर सकती है।

## नागपुर शालार्थ आईडी घोटाला: शिक्षा अधिकारी रवींद्र काटोलकर गिरफ्तार, करोड़ों का वित्तीय गबन उजागर



### नागपुर/यवतमाल

नागपुर और यवतमाल के शिक्षा विभाग को झकझोर देने वाले शालार्थ आईडी घोटाले में एक बड़ी कार्यवाही में शिक्षा अधिकारी रवींद्र शंकरराव काटोलकर को सायबर पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने वर्धा से गिरफ्तार किया है। काटोलकर पर आरोप है कि उन्होंने शालार्थ नामक सरकारी वेतन और कर्मचारी पहचान पोर्टल का भारी गबन किया, जिससे सरकारी खजाने को करीब ₹12 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि जब काटोलकर नागपुर ज़िला परिषद में प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने 39 फर्जी शालार्थ आईडी को सत्यापन के बिना मंजूर किया। इन नकली आईडी के आधार पर उन कर्मचारियों को वेतन जारी किया गया, जबकि वे वास्तव में पात्र नहीं थे। अधिकारियों ने कहा कि बिना जांच-पड़ताल के प्रस्तावों को मंजूरी देकर भारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया। घोटाले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि फर्जी आईडी के जरिए सरकारी वेतन का भुगतान अनियमित रूप से जारी रहा, जिससे राज्य को करोड़ों का वित्तीय झटका लगा। काटोलकर को मंगलवार को वर्धा से हिरासत में लिया गया और बाद में न्यायालय में पेश कर 25 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है ताकि उनसे पूछताछ और मामले की गहरी जांच जारी रखी जा सके। अब तक इस बड़े प्रकरण में कुल लगभग 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें शिक्षण उपसंचालक, अन्य अधिकारी, मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक और लिपिक शामिल हैं। यह मामला महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती और वेतन प्रणाली में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों को उजागर करता है, और जांच अभी भी जारी है।



## मुंबई: रियलिटी शो बिग के सेट मुंबई: रियलिटी शो बिग के सेट पर लगी आग

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य ब्लैकलिस्टेड कंपनी 'कोएम्प्ट एज्यु, टेक प्रा. लिमिटेड' को कैसे सौंपा गया, इस पर विवाद उभरा है। भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ (एनएसयूआई) ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय की टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ हुईं, जिससे ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आगामी तीन साल के लिए परीक्षा कार्य का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। एनएसयूआई का कहना है कि कंपनी के अनुभव प्रमाणपत्र, आवश्यक दस्तावेज़ और पहले का कामकाज ठीक से जाँचा नहीं गया, जबकि नियमों के अनुसार यह अनिवार्य था। एनएसयूआई के प्रतिनिधि कुलगुरु डॉ. मनाली क्षीरसागर से मिले और निवेदन में यह मुद्दा उठाया कि टेंडर में नियमों का उल्लंघन हुआ है और इससे छात्रों के हितों को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने एमओयू रद्द करने और जांच की मांग भी की। कुलगुरु ने जवाब में आश्वासन दिया कि उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर निष्पक्ष जांच की जाएगी और समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इस दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों जैसे अजित सिंह, आशिष मंडपे, प्रणय सिंह ठाकूर आदि उपस्थित रहे। छात्रों और शिक्षा जगत में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि परीक्षा कार्य से जुड़ी इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड बताकर भी कार्य सौंपा गया था, जिससे परीक्षा प्रक्रिया और छात्रों के अधिकारों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

## विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा: लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने

### संवाददाता | NEWS AGENCY

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रनों का रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली vs आंध्र के मुकाबले में हासिल की, जहाँ उन्होंने 330 पारियों में यह संकेतक पूरा किया, जबकि महान सचिन तेंदुलकर को यह उपलब्धि 391 पारियों में मिली थी। इससे कोहली इस प्रतिकूल रिकॉर्ड को तोड़कर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने यह मुकाम सबसे कम पारियों में हासिल किया। यह माइलस्टोन कोहली की बल्लेबाज़ी की निरंतरता और उत्कृष्टता को दर्शाता है, जिन्होंने केवल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ही नहीं बल्कि घरेलू लिस्ट-A क्रिकेट में भी अपनी पकड़ मजबूत रखी है। उन्हें अब सचिन तेंदुलकर के बाद लिस्ट-A में 16,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी की श्रेणी में शामिल होने का गौरव भी मिला है।



## इंडिगो संकट के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी: केंद्र ने 'अल हिंद एयर' व 'फ्लाईएक्सप्रेस' को NOC प्रदान किया

भारतीय विमानन क्षेत्र में नई दिशा का संकेत मिलता दिख रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने \*\*दो नई एयरलाइनों — अल हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस — को नागर विमानन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्रदान किया है। इस निर्णय का ऐलान नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने किया, जो इंडिगो एयरलाइंस द्वारा हाल में हुए व्यवधान (IndiGo crisis) के बाद लिया गया है। इससे घरेलू हवाई यात्रा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का प्रयास माना जा रहा है। इंडिगो संकट में दिसंबर की शुरुआत में हजारों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण यह स्पष्ट हो गया था कि घरेलू विमानन बाजार में कुछ कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता (duopoly) है, खासकर इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के बीच। इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने दो नई कंपनियों को NOC प्रदान किया है, ताकि हवाई यात्रियों को अधिक विकल्प और बेहतर सेवाएँ मिल सकें। 'अल हिंद एयर' को केरल स्थित अलहिंद समूह द्वारा प्रमोट किया गया है और यह घरेलू मार्गों पर उड़ान भरने की योजना तैयार कर रहा है। वहीं 'फ्लाईएक्सप्रेस' को हैदराबाद से संचालित किया जाएगा और यह भी भारतीय बाजार में प्रवेश की दिशा में अग्रसर है। दोनों एयरलाइनों को अब एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (AOC) जैसे अन्य औपचारिक चरणों को पूरा करना होगा, जिसके बाद वे व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू कर सकेंगी। इसके अलावा, शंख एयर नामक एक अन्य एयरलाइन, जिसे पहले ही NOC मिल चुका है, 2026 में उड़ान शुरू करने की संभावना रखती है। इन नई एयरलाइनों के आने से न केवल विकल्प बढ़ेंगे बल्कि विमानन बाजार में कीमतों में प्रतिस्पर्धात्मक दबाव और सेवा सुधार की उम्मीद भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर यह कदम भारतीय विमानन को अधिक विविध और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, खासकर तब जब हवाई यात्रा देश में तेजी से बढ़ रही है और यात्रियों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है।



## सत्ता समीकरणों का पुनर्गठन: महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर

संपादकीय...।

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर सत्ता समीकरणों के पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। हाल के समय में चुनावों से पहले और चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामने आए राजनीतिक संकेत यह दर्शाते हैं कि राज्य की राजनीति केवल चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि भविष्य की दिशा और रणनीति को लेकर व्यापक मंथन के चरण में प्रवेश कर चुकी है। बड़े राजनीतिक गठबंधनों को लेकर चल रही चर्चाएँ इसी बदलते परिदृश्य का संकेत हैं।

चुनावों से पहले जिन राजनीतिक संभावनाओं ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, उनमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच संभावित सहयोग की अटकलें प्रमुख रहीं। दोनों दलों की वैचारिक पृष्ठभूमि, मराठी अस्मिता पर जोर और शहरी राजनीति में प्रभाव को देखते हुए इस तरह की चर्चाओं ने स्वाभाविक रूप से राज्य की राजनीति में हलचल पैदा की। हालाँकि, ऐसे संकेतों को अंतिम राजनीतिक निर्णय मानना जल्दबाज़ी होगी, फिर भी यह स्पष्ट है कि बदलती परिस्थितियों में दल अपने विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर भी सत्ता संतुलन और सीटों के बंटवारे को लेकर विचार-विमर्श जारी है। विशेष रूप से बुहन्मुंबई महानगरपालिका जैसे बड़े और प्रभावशाली निकायों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच बातचीत को राजनीतिक विश्लेषक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं। गठबंधन राजनीति में सहयोग के साथ-साथ आपसी समन्वय और स्पष्ट समझौते की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, और इसी के तहत सीटों के चयन और भूमिका निर्धारण पर चर्चा होना असामान्य नहीं है।

इन घटनाक्रमों से यह संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब केवल एकध्रुवीय नहीं रही। विभिन्न दल और गठबंधन अपनी-अपनी सामाजिक आधारशिला, संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रणनीतियाँ तय कर रहे हैं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों को आत्ममंथन और पुनर्संतुलन का अवसर मिलता है।

स्थानीय निकाय चुनावों और सत्ता समीकरणों का आपसी संबंध भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। नगर निगम, नगर परिषद और अन्य स्थानीय संस्थाएँ सीधे जनता के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी होती हैं। ऐसे में इन निकायों में बनने वाले राजनीतिक समीकरण केवल सत्ता की दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रभावशीलता और विकास की गति के लिहाज से भी अहम होते हैं। यही कारण है कि बड़े दल इन चुनावों और संभावित गठबंधनों को भविष्य की राजनीति की बुनियाद के रूप में देखते हैं।

राजनीतिक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में स्थानीय सांसदों, विधायकों और क्षेत्रीय नेताओं की भूमिका भी बढ़ जाती है। वे न केवल अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने का कार्य करते हैं, बल्कि गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति केवल शीर्ष नेतृत्व तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर भी सक्रिय राजनीतिक सहभागिता देखने को मिलेगी।

हालाँकि, सत्ता समीकरणों के इस पुनर्गठन के साथ यह अपेक्षा भी जुड़ी है कि राजनीतिक दल जनता के मूल मुद्दों को प्राथमिकता दें। गठबंधन और रणनीति का उद्देश्य अंततः सुशासन, विकास और सामाजिक संतुलन होना चाहिए। यदि राजनीतिक संवाद केवल अंकगणित और सत्ता तक सीमित रह जाता है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँचने की आशंका बनी रहती है।

अंततः, महाराष्ट्र में सत्ता समीकरणों का पुनर्गठन एक बदलते राजनीतिक परिदृश्य की ओर संकेत करता है। यह परिवर्तन न तो पूरी तरह सकारात्मक है और न ही नकारात्मक, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राजनीतिक दल इस अवसर का उपयोग किस दिशा में करते हैं। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शिता, संवाद और जनहित के साथ आगे बढ़ती है, तो यह राज्य की लोकतांत्रिक परंपरा को और मजबूत कर सकती है। यही महाराष्ट्र की राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर दोनों हैं।

### WORLD NEWS | अमेरिका से मुनीर ने मांगी लीडरशिप

## हमास के खात्मे में सबसे आगे रहेगी पाकिस्तानी सेना? अमेरिका से मुनीर ने मांगी लीडरशिप

इस्लामाबाद/वॉशिंगटन | पाकिस्तान ने गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल स्ट्रेबिलाइजेशन फोर्स (ISF) में लीडरशिप जिम्मेदारी की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना ने हमास से हथियार छीनने के लिए बनाई जा रही फोर्स में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें कुछ शर्तें राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक हैं। यानि, पाकिस्तान कैसे लेकर गाजा में हमास के लड़ाकों से युद्ध करेगा। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान ने गाजा शांति सेना में शामिल होने का खुद ऑफर दिया है और अमेरिका इसका स्वागत करता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर गाजा में पाकिस्तान सेना को भेजने को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है।

मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से न्यूज-18 ने कहा है कि इस्लामाबाद चाहता है कि



अगर ISF को तैनात किया जाता है, तो उसकी सेना गाजा में ISF की कमान संभाले, जिसका नेतृत्व एक सीनियर पाकिस्तानी जनरल करे। हालांकि, पाकिस्तान को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी,

फिलहाल इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और ये अंतरराष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर करेगा कि उसे क्या रोल मिलता है। लेकिन पाकिस्तान ने गाजा में सेना भेजने के बदले अमेरिका से लंबे समय तक

आर्थिक समर्थन की मांग की है। गाजा में हमास से लड़ने पाकिस्तान भेजेगा सैनिक!

टॉप सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका और पाकिस्तान के सीनियर रक्षा अधिकारी ISF के संभावित गठन, जनादेश और ऑपरेशनल प्रोसेस को लेकर लगातार संपर्क में हैं। इसके तहत फिलहाल फोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी, फ्रेमवर्क क्या होगा और इसके नियम क्या होंगे, इसको लेकर जल्द ही हाईलेवल बैठक होने वाली है। सूत्रों के हवाले से न्यूज-18 ने बताया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर और US CENTCOM कमांडर के बीच जल्द ही एक बैठक होने की संभावना है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ अलग से डिप्लोमैटिक स्तर पर बातचीत भी होगी।

### World News | बांग्लादेश में यूनुस की होगी छुट्टी!

## बांग्लादेश में यूनुस की होगी छुट्टी! खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को PM बनाने की तैयारी?

### ● Reporter Name

ढाका: क्या बांग्लादेश में तारिक रहमान को अगला प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। पिछले कुछ दिनों से अहम संकेत मिलने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सीनियर नेता तारिक रहमान करीब दो दशक बाद देश लौट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट रहे हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बीएनपी, तारिक रहमान को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाली है? हालांकि अभी भी पार्टी के दूसरे सीनियर नेता सतर्क रूख अपनाए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में इस बाबत तेजी से चर्चा होने लगी है।

न्यूज 18 ने बीएनपी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा है कि पार्टी के भीतर "कुछ संभावनाओं" पर गंभीरता से विचार चल रहा है, हालांकि अंतिम फैसला पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को लेना है, जो इस वक्त भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी सेहत को लेकर चिंता बरकरार है,



लेकिन पार्टी के नेताओं का दावा है कि वह अब भी राजनीतिक घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 ने दावा किया है कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले भी वह रणनीतिक फैसलों में पूरी तरह सक्रिय थीं और पार्टी की दिशा तय करने में उनकी भूमिका निर्णायक बनी हुई है।

क्या तारिक रहमान बनेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री? तारिक रहमान ऐसे वक्त में ढाका लौट रहे हैं जब देश हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया गया है। जबकि जमात-ए-इस्लामी का तेजी से उभार हो रहा है। लिहाजा, बीएनपी के

लिए इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि BNP के लिए यह महज एक और चुनाव नहीं, बल्कि करीब 15 वर्षों बाद सत्ता में वापसी का संभावित रास्ता है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि ऐसे समय में अगर तारिक रहमान को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो लोग भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़ सकते हैं।

### बांग्लादेश में यूनुस की होगी छुट्टी!

हालांकि कई नेता तारिक रहमान के नाम पर पार्टी में कुछ नेताओं का विरोध भी है। विरोध करने वाले नेता वंशवाद की राजनीति की दलील दे रहे हैं। खासकर बदलते हालात में युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या देखकर। उनका कहना है कि ऐसा करने पर विपक्षी, वंशवाद की राजनीति पर पार्टी को घेर सकते हैं। इनका तर्क ये भी है कि क्या विरासत के आधार पर मतदाता, तारिक रहमान को स्वीकार करेंगे? रिपोर्ट के मुताबिक, बीएनपी में तारिक रहमान को लेकर दुविधा बढ़ती जा रही है।

जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन करेगी BNP? न्यूज 18 ने बीएनपी के एक सीनियर नेता के हवाले से कहा है कि पार्टी कई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रही है, जिसमें एक संभावना गठबंधन को लेकर भी है। इस हिंसा से बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन करने पर विचार कर सकती है। वहीं, पार्टी के एक और अन्य सूत्र ने कहा है कि अवामी लीग के मुकाबले से बाहर होने की वजह से जमात-ए-इस्लामी, जिसके बाद संगठन के स्तर पर काफी गहराई है, उसके साथ गठबंधन कई निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि उन्होंने जमात से गठबंधन करने पर कुछ जोखिमों का भी जिक्र किया है। उनका मानना है कि गठबंधन अगर होता भी है, फिर भी बीएनपी और जमात के बीच वैचारिक स्तर पर काफी गंभीर मतभेद हैं, जो सरकार बनाने पर और गहरा सकते हैं। इसके अलावा, जमात के साथ गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी शांति स्वरूप होगी। इसीलिए बीएनपी फूक-फूककर कदम रख रही है।



वॉशिंगटन: अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी एक सालाना रिपोर्ट में भारत के 4 पड़ोसी देशों में चीन सैन्य तैयारी को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पेंटागन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के ग्वादर में नेवल बेस बना रहा चीन अब बांग्लादेश में भी सैन्य ठिकाना बनाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना पीएलए बहुत सक्रियता के साथ अतिरिक्त सैन्य सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार रही है ताकि जमीनी सेना की मदद से नौसैनिक और हवाई ताकत का प्रदर्शन किया जा सके। इन देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका और

## भारत के 4 पड़ोसी देशों में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है चीन, अमेरिका ने दी चेतावनी

बांग्लादेश के अलावा करीब एक दर्जन अन्य देश शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अब तक पाकिस्तान को 20 जे-10 सी फाइटर जेट दिए हैं।

पेंटागन ने कहा है कि चीन अंगोला, बांग्लादेश, म्यांमार, क्यूबा, गिनी, इंडोनेशिया, केन्या, मोजाबिक, नामिबिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सेशेल्स, सोलोमन द्वीप समूह, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, यूएई और वनातू में सैन्य सुविधा केंद्र बनाना चाहता है। पीएलए की सबसे ज्यादा इच्छा मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और अन्य अफ्रीकी तथा मध्य पूर्व के इलाकों में सैन्य पहुंच बनाने की है। चीन चाहता है कि इन जगहों पर उसका सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बना रहे। चीन मलक्का स्ट्रेट को अपना सबसे बड़ा चोक प्वाइंट मानता है जहां अमेरिका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से

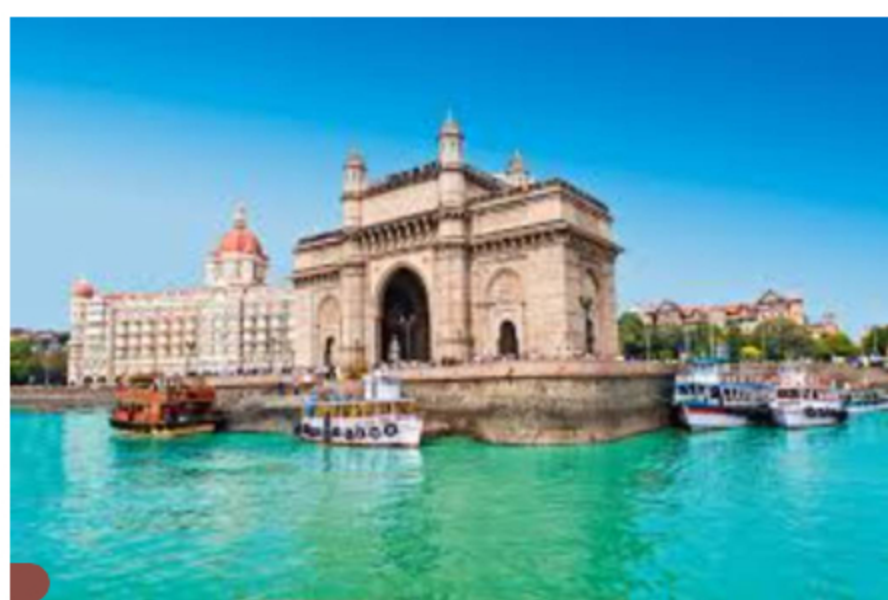
भारतीय नौसेना उसे घेर सकते हैं।

चीन और बांग्लादेश में सैन्य संबंध काफी मजबूत

वहीं अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश चीन से जे-10 सी फाइटर जेट खरीदने की इच्छा रखता है। यह वही चीनी लड़ाकू विमान है जिसका पाकिस्तान ने भारत के राफेल के खिलाफ इस्तेमाल किया था। बांग्लादेश शेख हसीना के जमाने से ही चीन से अपनी सैन्य दोस्ती को मजबूत कर रहा था। बांग्लादेश चीन के सैन्य वाहनों और VT-5 लाइट टैंक का बड़ा ग्राहक है। साल 2024 में चीन ने बांग्लादेश को मिंग क्लास की दो पनडुब्बी और दो युद्धपोत सौंपा था। चीन मोहम्मद यूनूस सरकार आने के बाद पाला बदल चुका है और उनको खुलकर अपना समर्थन दे रहा है।

अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और इसी दौरान बीजिंग पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंधों को ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसमें कहा गया है कि चीन भारत के साथ अपने रिश्ते में गर्मजोशी इसलिए बढ़ा रहा है ताकि भारत और अमेरिका में दोस्ती को मजबूत होने से रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से चीन ने एलएससी पर भारत संग तनाव को कम किया है। बता दें कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते में तनाव कम हुआ है। वीजा सवाप फिर से शुरू हो गई हैं। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अरुणाचल को चीन ने अपने 'कोर इंटरैस्ट' में शामिल किया है जो संप्रभुता से जुड़ी हुई है।





# महाराष्ट्र विशेष

## कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Thursday 25th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 239 , पृष्ठ 03

### लातूर महापालिका

चुनाव: 3.21 लाख

मतदाता 18 प्रभागों से 70

सदस्यों का चुनाव करेंगे



लातूर महानगरपालिका चुनाव की तैयारियाँ जोरशोर से चल रही हैं, जिसमें कुल 3,21,354 मतदाता 18 प्रभागों से 70 सदस्यों का चयन करेंगे। मतदाता सूची अंतिम रूप दे दी गई है और इसी के आधार पर इच्छुक उम्मीदवार प्रचार एवं तैयारी में जुट गए हैं।

चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही महापालिका प्रशासन ने अनधिकृत पोस्टरों और फलक को हटाने का काम शुरू कर दिया है। प्रमुख राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने अपने अपने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं, जिससे चुनावी सरगमी बढ़ गई है। अब सभी की नजर आगामी मतदान पर है, जो इस महापालिका में नए प्रतिनिधियों के चयन का मार्ग तय करेगा।

### बेंबळा सिंचाई घोटाले में फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र— कंत्राटदारों पर केस दर्ज



यवतमाल जिले के बेंबळा सिंचाई परियोजना घोटाले में अब एक नया मोड़ आया है, जहाँ जांच में यह पता चला है कि कई ठेकेदारों ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र का उपयोग कर काल्वे का काम पाने के लिए आवेदन किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच में यह बात सामने आई कि इन प्रमाणपत्रों को नौकरी योग्य अनुभव दिखाने के लिए गलत तरीके से पेश किया गया था, जिससे सरकारी एजेंसियों को धोखा पहुंचाया गया।

न्यायालय के आदेश के बाद 2018 से इस मामले की जांच चल रही थी और अब तीन ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी व दस्तावेज़ फर्जी साबित करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

घोटाले में करोड़ों रुपये के सरकारी कार्य शामिल बताए जा रहे हैं और इसके तहत फर्जी दस्तावेज़ पेश करने के आरोप में आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

Maharashtra News | 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स इकट्ठा,

## 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स इकट्ठा, शिवसेना UBT-मनसे में गठबंधन, फडणवीस-एकनाथ शिंदे ने दी प्रतिक्रिया

**मुंबई** | महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लगभग 20 साल के राजनीतिक अलगाव के बाद एक साथ आए और शिवसेना (UBT) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के बीच राजनीतिक गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया गया। यह घोषणा विशेष रूप से मुंबई के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों समेत अन्य नगरपालिका चुनावों को ध्यान में रखकर की गई है।

दोनों नेताओं ने मुंबई के वोरली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब समय आ गया है कि वे मराठी लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट



हों। उद्धव ठाकरे ने कहा, “हम साथ आए हैं और साथ रहेंगे। यह गठबंधन महाराष्ट्र और मुंबई के हित में है।” राज ठाकरे ने भी कहा कि महाराष्ट्र की भलाई किसी भी व्यक्तिगत मतभेद से बड़ी है, इसलिए उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया। इस गठबंधन की घोषणा से राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने

इस गठबंधन को “राजनीतिक अवसरवादिता” करार देते हुए कहा कि यह केवल सत्ता में बने रहने की कोशिश है। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी इस फैसले पर तीखा हमला किया और इसे जनता को भ्रमित करने की कोशिश बताया।

राज ठाकर ने कहा कि यह गठबंधन केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि मराठी

गौरव व मराठी संस्कृति को और मजबूत करने के लिए है और उन्होंने कहा कि मुंबई समेत राज्यभर में मराठी लोगों की आवाज़ को विभाजित नहीं होने देंगे। उद्धव-राज ने बालासाहेब ठाकरे की स्मृति का सम्मान भी किया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन महाराष्ट्र की पुरानी राजनीति को नया रूप दे सकता है, खासकर उन नगर निगमों में जहां मराठी पहचान और स्थानीय मुद्दे प्रभावी हैं। आगामी चुनावों में इस नए समीकरण का मतदाताओं के रुझान पर गहरा असर पड़ने की संभावना है और राजनीतिक घटनाक्रम को और भी मोड़ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

## ठाकरे बंधुओं की युती के बीच संभाजीनगर में राजनीतिक भूचाल: मनसे जिल्हाध्यक्ष शिंदे सेना में, शहराध्यक्ष भाजपा में शामिल!

छत्रपती संभाजीनगर में ठाकरे बंधुओं (उद्धव और राज ठाकरे) द्वारा गठबंधन की घोषणा के बाद भी राजनीति उलट दिशा में आगे बढ़ रही है। ठाकरे गुट के ऐतिहासिक सहयोग की खबर के बीच मनसे के छत्रपती संभाजीनगर जिला अध्यक्ष सुमित खांबेकर ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना (शिंदे सेना) में प्रवेश किया है। खांबेकर ने शहर और जिले के हित में यह कदम उठाने की बात कही है।



साथ ही, मनसे के शहर अध्यक्ष आशिष सुरडकर और गजन गौडा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होकर अपना राजनीतिक घर बदल लिया है। ये सभी प्रवेश महाराष्ट्र में आगामी महापालिका चुनाव से पहले हुए हैं, जिससे मनसे को स्थानीय स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है।

इन नेताओं का शिंदे सेना और भाजपा में जाना राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी इस कदम को लेकर चर्चाएँ तेज हैं। खांबेकर के इस फैसले का असर आगामी चुनावों में कैसे दिखता है, यह अब राजनीतिक विश्लेषकों की निगाह में है।

## परभणी महापालिका चुनाव: पहले दिन 550 नामांकन पत्र खरीदे गए, लेकिन कोई आवेदन दाखिल नहीं हुआ



परभणी महानगरपालिका के महापालिका चुनाव 2026 के नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन मतदाता और उम्मीदवारों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया दिखाई दी। शहर की 16 प्रभागों में 65 पार्सद पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत पहले दिन कुल 550 नामांकन पत्र खरीदे गए, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया।

सोमवार को सुबह से ही प्रभाग समिति कार्यालयों पर उम्मीदवारों और समर्थकों की हलचल देखने को मिली, जिन्होंने नामांकन पत्र खरीदने के लिए लंबी कतारें लगाईं। राजस्व और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ 19 पृष्ठों वाले फॉर्म को खरीदने का उत्साह अच्छा रहा, लेकिन फिर भी शाम तक

कोई भी फॉर्म जमा नहीं हुआ।

चुनाव प्रशासन ने नामांकन जमा करने के लिए पाँच विभिन्न केंद्र निर्धारित किए हैं: प्रभाग समिति क कल्याण मंडपम, नटराज रंगमंदिर, पंचायत समिति, महापौर कक्ष और बी. रघुनाथ सभागृह। इन सभी स्थानों पर पूर्व-तपासणी टीम, चुनाव निर्णय अधिकारी और कर्मचारी सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक दृढ़ता से उपस्थित रहे और उम्मीदवारों को प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी।

प्रत्येक प्रभाग के लिए अलग-अलग स्थानों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई थी, ताकि किसी भी तरह की अराजकता न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख तक उम्मीदवार अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं यदि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों और शपथपत्रों के साथ आवेदन करते हैं।

इस अनोखी स्थिति से जहाँ चुनावी प्रक्रिया की रुचि का संकेत मिलता है, वहीं प्रत्याशियों के नामांकन नहीं देने से प्रतिस्पर्धा के स्तर पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में उम्मीदवारों की भागीदारी और वास्तविक नामांकन संख्या से महापालिका चुनाव के नक्शे पर बड़ा असर पड़ेगा।

## 1988 में संभाजीनगर नगरपालिका चुनाव का थ्रिलर: एक उम्मीदवार 'रॉबिनहुड' बनकर जीत गया जनता के समर्थन से



देखा, क्योंकि उसने न तो बड़ी धनराशि खर्च की और न ही भारी-भरती राजनीतिक मशीनरी का सहारा लिया। स्थानीय लोगों ने अपने खुद के संसाधनों से प्रचार किया और उसे समर्थन दिया, जिससे उसने बड़े-मोटे राजनेताओं को हराया।

इस चुनाव ने यह दर्शाया कि सच्चा राजनीतिक समर्थन महँगाई और खर्च से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और मेहनत से आता है। उस समय इस जीत को राजनीतिक विश्लेषकों ने जनता की जागरूकता और पारंपरिक राजनीति का प्रतिकार माना। आज भी यह घटना लोकशाही की शक्ति का प्रतीक है — जब सामान्य नागरिक अपने दम पर जीत सकता है और बड़े दलों की नीतियों को चुनौती दे सकता है। यह चुनाव न केवल एक थ्रिलर परिणाम था, बल्कि जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना।

उस उम्मीदवार को जनता ने 'रॉबिनहुड' के रूप में

## हिंगोली: ट्रांसफॉर्मर चिंगारी से 12 एकड़ गन्ना जला, किसानों ने मुआवजे की मांग की



हिंगोली जिले के औंढा नागनाथ तालुका के पुरजळ इलाके में गन्ना किसानों के लिए भारी हादसा सोमवार 20 दिसंबर को दोपहर के समय हुआ, जब एक खेत में ट्रांसफॉर्मर से उड़ती चिंगारी ने आग पकड़ ली और लगभग 12 एकड़ गन्ना की फसल को राख कर दिया। किसान इस घटना से गहरे आहत हैं और उन्हें सरकार से तात्कालिक मुआवजे की मांग है।

शहर के पास स्थित खेत में गन्ना की फसल कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन उस खेत के नज़दीक लगे वीज़रोहित्र (ट्रांसफॉर्मर) से अचानक स्पार्क (चिंगारी) उड़कर पड़ी और सूखे गन्ने ने तुरंत आग पकड़ ली।

कुछ देर में ही आग ने पूरे क्षेत्र को अपनी जद में ले लिया। शोर मचते ही आसपास के किसान भागे, लेकिन थोड़ी देर में आग का फैलना रोक पाना कठिन हो गया, क्योंकि सूख चुका गन्ना तेजी से जलता है।

इस आग में किसानों का अतोनात नुकसान हुआ—खेत गट क्रमांक 8 में इशार्द आलम के 9 एकड़ और सरताज आलम के 3 एकड़ गन्ना खेत पूरी तरह से जलकर राख हो गए। किसानों का कहना है कि इस नुकसान से उनके परिवारों की आजीविका मुश्किल में पड़ गई है और अब उन्हें जीवनयापन के साधन बचे नहीं हैं।

किसानों ने आरोप लगाया कि पास की चीनी मिल ने दो महीने से भी अधिक समय से गन्ना नहीं लिया, जिसके कारण गन्ना कटाई के लिए तैयार पड़ा रहा और सूखकर आग के लिए संवेदनशील स्थिति में बदल गया। अगर गन्ना समय पर मिल ले लेती तो यह हादसा टाला जा सकता था, उनका कहना है।

आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल को बुलाया गया था, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण आग नियंत्रण में देर हो गई, जिससे नुकसान और बढ़ गया। किसानों ने प्रशासन से पूरे नुकसान का मानवीय मुआवजा और फसल बीमा के तहत राहत देने की मांग की है।





## महापालिका चुनाव: पहले दिन 663 नामांकन पत्रों की बिक्री



### संवाददाता |

नांदेड | महानगरपालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही इच्छुक उम्मीदवारों में हलचल देखने को मिली। पहले ही दिन कुल 663 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया।

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए शहर में 7 ज़ोन बनाए गए हैं। इनमें वर्कशॉप स्थित ज़ोन से 126, श्री गुरु गोविंद सिंहजी स्टेडियम से 74, कामागार कल्याण भवन (लेबर कॉलोनी) से 125, कपास

अनुसंधान केंद्र देगलूर नाका से 112, उर्दू घर मदिनानगर से 81, महाराजा रणजीत सिंहजी मार्केट क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 4 से 70 और क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 6 सिडको से 75 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। इस तरह पहले दिन कुल 663 नामांकन पत्र बेचे गए।

हालांकि, सभी ज़ोन में एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। जानकारों के अनुसार, प्रत्याशी आमतौर पर अंतिम दिनों में ही नामांकन दाखिल करना पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।

### Nanded Politics | पूर्व महापौर सहित कई नेता AIMIM में शामिल

## नांदेड में कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध, पूर्व महापौर सहित कई नेता AIMIM में शामिल

नांदेड (संवाददाता) : नांदेड-वाघाला शहर महानगरपालिका चुनाव की सरगमी तेज होते ही राजनीतिक उठापटक भी चरम पर पहुंच गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की पारंपरिक मानी जाने वाली मुस्लिम वोट बैंक में दरार पड़ती दिख रही है। कांग्रेस के पूर्व महापौर सहित मुस्लिम समाज के कई पूर्व नगरसेवकों ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) में सार्वजनिक रूप से प्रवेश किया है।



महानगरपालिका चुनाव में AIMIM की एंटी से कांग्रेस के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सत्ता समीकरण बदलने के लिए सत्ताधारी दलों की ओर से सुनियोजित रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की मुस्लिम और बौद्ध वोट बैंक को तोड़ने के उद्देश्य से AIMIM और वंचित बहुजन आघाड़ी को आगे किया जा रहा है।

हाल ही में हुई नगर परिषद चुनावों का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि AIMIM और वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और इसका अप्रत्यक्ष लाभ भाजपा को मिला। भोकर नगर परिषद चुनाव में यदि AIMIM का उम्मीदवार मैदान में

नहीं होता, तो कांग्रेस की जीत संभव थी, यह मतदान आंकड़ों से स्पष्ट होने का दावा किया जा रहा है।

इसी पृष्ठभूमि में देगलूरनाका परिसर के मुस्लिम समाज के कई प्रमुख नेताओं ने AIMIM में प्रवेश किया है। इनमें

कांग्रेस के पूर्व महापौर मसूद अहमद खान, पूर्व उपमहापौर अब्दुल शमीम, पूर्व नगरसेवक अब्दुल हबीब वागवान, चांद पाशा कुरेशी और अब्दुल रशीद शामिल हैं। AIMIM नेता सैयद मोईन ने सभी का स्वागत किया। प्रवेश के बाद पुराने नांदेड इलाके में AIMIM कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया।

कांग्रेस के भीतर लगातार हो रही टूट-फूट से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पार्टी नेतृत्व पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व 'कुंभकर्णी नींद' में है। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माने जाने वाले नांदेड जिले में अब पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में नांदेड-वाघाला शहर महानगरपालिका के आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की संभावनाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों और बदलते समीकरणों को देखते हुए यह संदेह जताया जा रहा है कि नांदेड-वाघाला सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस अपनी उपस्थिति कितनी प्रभावी ढंग से बनाए रख पाएगी।



### माहूर में महिला पर तेंदुए का हमला, गंभीर घायल

नांदेड (संवाददाता): माहूर तहसील के बामनगुडा गांव में मंगलवार, 23 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे खेत में काम कर रही एक महिला पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने तेंदुए को नरभक्षी घोषित कर उसे तुरंत पकड़ने की मांग की है।

35) अपने पति, बेटे और एक पड़ोसी के साथ खेत में कपास तोड़ने का काम कर रही थीं। इसी दौरान किसी काम से पति घर चले गए। तभी खेत से सटे जंगल से आए तेंदुए ने अचानक महिला पर झपट्टा मार दिया और उसके चेहरे व गर्दन को जबड़े में पकड़कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला के गाल, माथे और गर्दन पर गहरे घाव आए हैं।

महिला के बेटे और साथ मौजूद व्यक्ति के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, जिससे महिला की जान बच सकी। घायल महिला को पहले सिंदखेड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया गया, बाद में माहूर ग्रामीण अस्पताल और फिर यवतमाल रेफर किया गया।

घटना के बाद किसानों और नागरिकों में भारी भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए को तत्काल पकड़ने की मांग की है, अन्यथा जानमाल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लता सुरेश तोडसाम (उम्र

## महाराष्ट्र सरकार आपातकाल में जेल गए बंदियों का सम्मान करेगी



### संवाददाता | Nanded

महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल (1975-77) के दौरान जेल में बंद रहे महाराष्ट्रीयनों का सम्मान करने का बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने इस वर्ष 22 दिसंबर को एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत उन लोगों को मानधन देने का प्रावधान किया गया है जिन्होंने आपातकाल के समय तिहाड़ समेत विभिन्न जेलों में बंदीवासी का अनुभव किया। कुल 3,813 व्यक्तियों को जनवरी और फरवरी 2026 के लिए दो महीने का वित्तीय मानधन दिया जाएगा, जिसका

कुल बजट लगभग ₹21.20 करोड़ है। इस निर्णय का उद्देश्य उन लोकतंत्र प्रेमियों का सम्मान करना है जिन्होंने सरकारी कार्रवाई के दौरान अपनी आज़ादी का बलिदान दिया। वितरण की जिम्मेदारी संबंधित जिल्हाधिकारियों तथा अधिकारी करेंगे ताकि यह सहायता समय पर प्रभावित लोगों तक पहुंच सके। सरकार का यह कदम आपातकाल की अप्रिय ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए नए साल की शुरुआत में सम्मान देने जैसा माना जा रहा है।

## नांदेड: सक्षम ताटे हत्या प्रकरण – गर्लफ्रेंड और मां ने जिल्हाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदहन का प्रयास, पुलिस पर मामला दर्ज करने की मांग



नांदेड में सक्षम ताटे हत्या प्रकरण से जुड़ी एक संवेदनशील और चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसमें मृतक की गर्लफ्रेंड आचल ममीडवार और उसकी मां ने जिल्हाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदहन का प्रयास किया। दोनों ने यह कदम इस बात के विरोध में उठाया कि सक्षम ताटे की हत्या के मामले में शामिल दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों ने सक्षम की हत्या में सीधे-सीधे भूमिका नहीं निभाई, पर उनकी गैर-सक्रियता और कथित प्रोत्साहन के कारण न्याय नहीं मिल रहा है।

यह आत्मदहन का प्रयास तब हुआ जब आचल और सक्षम की मां ने वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी मांगें पहुंचाने की

कोशिश की, लेकिन उनके किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। दोनों ने जिला प्रशासन से उन दो पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की। ज्वलनशील पदार्थ लेकर आत्मदाह के प्रयास पर पुलिस समय रहते हस्तक्षेप कर उन्हें रोका, अन्यथा हालात और गंभीर हो सकते थे।

सक्षम ताटे की हत्या 27 नवंबर को नांदेड शहर के जुनागंज इलाके में हुई थी। यह मामला प्रेम-और जातीय विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें आचल के पिता, भाइयों और अन्य आरोपियों पर सक्षम की हत्या का आरोप है। सभी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार और समर्थक अब न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस पर निष्पक्ष जांच करने का दबाव बना रहे हैं।

इस पूरी घटना ने प्रशासन एवं पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाए हैं, साथ ही यह दिखाया है कि पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा पाने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार है।

## पूर्व विधायक अनिल गोते की PIL बेनामी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमा 1 लाख रुपये जब्त किए

### संवाददाता |

बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने पूर्व विधायक अनिल गोते के खिलाफ महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें जनहित याचिका (PIL) दाखिल करते समय जमा किया गया 1 लाख रुपये का सुरक्षा जमा जप्त कर दिया गया। अनिल गोते ने धुळे के दोडाईचा इलाके में दादासाहेब रावळ सहकारी बैंक के कथित अनियमितताओं के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने पाया कि वे मूल तक्रारकर्ता नहीं थे, न ही वे किसी निवेशक या बैंक के क्षेत्र में निवासी हैं, इसलिए उन्हें यान्यायिक हित (locus standi) नहीं माना गया।

औरंगाबाद बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय का समय व्यर्थ नहीं किया जा सकता, इसलिए जमा की गई धनराशि को जप्त कर अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए देने का आदेश दिया। इस फैसले के अनुसार, जप्त राशि का आधा हिस्सा नांदेड के महिला आश्रय गृह और आधा हिस्सा अरबी के छात्र कल्याण प्रतिष्ठान को आवंटित किया जाएगा। यह मामला इस बात को स्पष्ट करता है कि जनहित याचिका तभी प्रभावी होती है जब याचिकाकर्ता का प्रकरण से प्रत्यक्ष संबंध हो, अन्यथा अदालत सरस्ती से कार्यवाही करती है।



## ‘किंगमेकर’ पूर्व विधायक माधवराव पाटिल जवळगावकर का चला जादू

## हिमायतनगर नगरपंचायत पर कांग्रेस का परचम, ‘किंगमेकर’ पूर्व विधायक माधवराव पाटिल जवळगावकर का चला जादू

हिमायतनगर (संवाददाता): हिमायतनगर नगरपंचायत के लिए हुए बेहद चुर्गंगी और रोचक चुनाव में आखिरकार कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए बाज़ी मार ली है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शेख रफीक शेख महेबूब ने 2366 मतों की भारी बढ़त के साथ नगराध्यक्ष पद पर विजय हासिल की। इस जीत के साथ ही नगरपंचायत में दूसरी बार कांग्रेस का झंडा लहराया है।

इस जीत के पीछे पूर्व विधायक माधवराव पाटिल जवळगावकर की रणनीति और संगठनात्मक ताकत को अहम माना जा रहा है। जवळगावकर ने चुनाव में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ नए चेहरों को भी मौका दिया, जो पूरी तरह सफल साबित हुआ। कांग्रेस

के कुल 8 नगरसेवक निर्वाचित हुए हैं। पिछले 25 वर्षों से जवळगावकर की मजबूत कार्यकर्ता फौज इस जीत की नींव मानी जा रही है। नतीजों से यह भी स्पष्ट हुआ कि युवा और महिला मतदाताओं ने कांग्रेस को खुलकर समर्थन दिया।

भाजपा ने नगरपंचायत में पहली बार प्रवेश करते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार डॉ. राजेंद्र वानखेडे 4281 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दर्शना चायल, आशीष सकवान और भारत डाके भाजपा से विजयी हुए। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने बिना बड़ी सभाओं और प्रचार के 3 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। वार्ड 9 से सुचिता राठोड और वार्ड 12 से विठ्ठल ठाकरे की जीत

उल्लेखनीय रही।

राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के सरदार खान दूसरी बार निर्वाचित हुए, जबकि शिंदे गुट से सुभाष बलपेलवाड और अरुणा मुद्देवाड ने जीत हासिल की।

हालांकि, चुनाव के दौरान जाति, धर्म और धन के खुले इस्तेमाल को लेकर नागरिकों में चिंता भी देखी गई। लोकतंत्र के सामने खड़ी इन चुनौतियों पर चर्चा तेज है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने से अब नगरपंचायत का प्रशासन एकहाती रहेगा, जबकि भाजपा, उद्धवसेना और शिंदेसेना से एकजुट होकर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की अपेक्षा है।